

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना संख्या-234 / 2023
(अपील संख्या :-1106 / 2009)

सुरेन्द्र कुमार शर्मा

—अपीलार्थी / प्रार्थी

बनाम

श्री महावीर प्रसाद महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर।

—अप्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 28.12.2023
विनिश्चय की दिनांक : 06.11.2024

उपस्थित :

प्रार्थिया की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका इस अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील संख्या 1106 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2012 की पालना नहीं करने व अधिकरण के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करना बताते हुए दिनांक 28.12.2023 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2012 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया था :-

“उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश पत्र संख्या एफ.2(378)स्था./पमुं./2009/7431 दिनांक 22.09.2009 (प्रदर्श-ए-12) को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 16.09.2009 (प्रदर्श-ए-11) द्वारा जारी स्थाई वरिष्ठता सूची वर्ष 2009 में अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 1 पर दर्शाये गये श्री वीरेन्द्र कुमार के नीचे तथा क्र.सं. 2 पर दर्शाये गये श्री अलीशेर के नाम के ऊपर अर्थात् क्र.सं. 2 पर दर्शाते हुए संशोधित करें। तदानुसार अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदौन्नति (यदि अपीलार्थी अन्यथा पदौन्नति का पात्र

हो) समस्त पारिणामिक लाभ सहित उस दिनांक से प्रदान की जाये, जिस दिनांक से उससे कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है।”

2. प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि उसने निर्णय की पालना हेतु दिनांक 06.04.2012 को प्रत्यर्थागण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श-2 है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि 12 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अधिकरण के आदेश की पालना नहीं की है एवं अधिकरण के आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 15957/2013 दायर की गई है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने निर्णय की पालना जानबूझ नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिकरण के आदेश दिनांक 27.03.2012 की पालना नहीं किये जाने के कारण अवमानना प्रकरण बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जावे।
3. इस अवमानना आवेदन की पालना करने हेतु दिनांक 06.02.2024 को प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी किए गए थे तथा दिनांक 20.03.2024, 03.05.2024, 04.07.2024, 27.08.2024, 18.10.2024 एवं 06.11.2024 को राजकीय अधिवक्ता को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकरण के निर्णय दिनांक 27.03.2012 की पालना नहीं की है और ना ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है तथा ना ही किसी प्रकार जवाब प्रस्तुत किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. यह अवमानना याचिका दिनांक 28.12.2023 को पेश की गयी थी। उसके बाद दिनांक 20.03.2024, 03.05.2024, 04.07.2024, 27.08.2024, 18.10.2024 एवं 06.11.2024 की तिथियां अप्रार्थीगण को आदेश की पालना के लिये दी गयी थी, परन्तु अप्रार्थी विभाग ने आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थागण/अप्रार्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थागण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना

करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

6. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी-प्रत्यर्थागण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 27.03.2012 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी-अपीलार्थी की अवमानना याचिका स्वीकार की जाकर इस अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस संदर्भ में अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम-1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्रवाई के विचाराणार्थ प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)